अफ़ग़ानिस्तानः बीसवीं सदी सुधार के आईने में

शाह अमानुल्लाह ने "निज़ामनामा" पर दस्तख़त कर बाल विवाह पर रोक लगा दी। निक़ाह मे कुबूलनामे की उम्र 13 कर दी थी, बहुविवाह पर रोक लगा दी, चादर को हटाने का हुक्म दिया, विधवा विवाह को क़ानूनी हैसियत अता की और मेहर को क़ानूनी ज़ामा पहना दिया।

भगवान प्रसाद सिन्हा

द्वितीय एंग्लो-अफ़ग़ान जंग के बाद ब्रिटिश प्रभाव में आकर या आधुनिकता की हवा से प्रेरित होकर शाह हबीबुल्लाह ने सामाजिक -सांस्कृतिक सुधारों की दिशा में क़दम उठाने शुरू किए। उसी समय 1911 में अफ़ग़ानिस्तान के शाही परिवार के ही एक दानिशवर रहनुमा, मुहम्मद बेग तज़ी द्वारा "सिराज अल-अख़बार निकाला जाने लगा।

इस पत्रिका ने अपने सफ़े के बेसतर हिस्से को हबीबुल्लाह के सामाजिक सुधारों को अर्पित कर दिया। तज़ी यद्यपि शाही ख़ानदान से तआल्लुक़ रखते थे लेकिन वे तरक़्क़ीपसंद ख़्यालों के मुरीद थे। उन्होंने पत्रिका के माध्यम से दम भर हबीबुल्लाह का साथ दिया और उसके अच्छे असरात दिखने भी लगे जो आगे कई घटनाओं के योग से और परवान चढे।

यह तज़ी की पत्रिका थी जिसने सबसे पहले अफ़ग़ानियों को बताया कि "वह समाज कभी तरक़्क़ी नहीं कर सकता जबतक कि उसके सुधार-कार्यसूची की हृदयस्थली में औरतों की शिक्षा को ज़गह नहीं दी गई हो"! तज़ी से प्रभावित होकर दमिश्क में पैदा उस वक़्त की एक विदुषी आसमां रश्मिया ख़ानम ने तज़ी से निक़ाह किया । आसमां रश्मिया ख़ानम ने बाद में विश्व की ख्यातिप्राप्त महिलाओं पर एक शृंखला निकालना शुरू की थी।

इस शाही दंपत्ति से ही सुरैया तज़ी का जन्म हुआ जिनकी शादी बाद में शाह अमानुल्लाह से हुई। इतने तरक़्क़ीपसंद ख़्याल का परिवार जब अफ़ग़ानिस्तान पर तख़्तनशीन हुआ तो यह स्वभाविक था कि शाह हबीबुल्लाह ने सुधार के जो बीज अफ़ग़ानिस्तान के समाज में बोए थे वह एक फलदार दरख़्त बनकर शाह अमानुल्लाह के समय में पूरे देश पर छा जाए।

शाह हबीबुल्लाह की 1919 में मृत्यु हो गयी । उनके बेटे अमानुल्लाह शाह बने। तीसरे एंग्लो अफ़ग़ान जंग में अंग्रेजों की शिकस्त के बाद जब अमानुल्लाह ताक़तवर बनकर उभरे तो उन्होंने अफ़ग़ानिस्तान में भी सामाजिक-धार्मिक सुधार के क़दम उठाने शुरू किये थे। 1921 में दोनों माँ बेटी ने एक अख़बार निकालना शुरू किया। 1925 तक इस अख़बार का ज़ल्वा क़ायम रहा। इस अख़बार का नाम इरशाद अल- निस्वान था जिसका मतलब होता है "औरतों का गाइड"!

अपनी बीबी और सास से मुतासिर होकर अमानुल्लाह ने सुधार के कामों में तेज़ी लानी शुरू जो उनके पिता के द्वारा शनैः शनैः चलाए जा रहे थे। 1921 में ही बेगम सुरैया और रश्मियाख़ानम ने देश में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला! नाम रखा मक़तबेमस्तुरात। इसके तहत उन्होंने औरतों की तालीम, सेहत और दीगर अधिकारों के मुतल्लिक़ भी सुधार के कार्यक्रम अपनाने की क़वायद को अंज़ाम दिया। एक वक़्त ऐसा भी आया था जब पड़नेवाली लड़कियों की तादाद मक़तबेमस्तुरात में 800 तक पहुँच गयी थी। आगे चलकर औरतों के बुर्के पहनने पर पाबंदी आयद कर दी गई। उनके लिए पहला अस्पताल खोला गया। । यूरोप से उस्ताद मंगाए गए और अफ़ग़ानिस्तान से औरतों को यूरोप भेजा गया। शादी की न्यूनतम उम्र सीमा को बढ़ाकर सोलह बरस की गई। दहेज़ की बढ़ती प्रथा को रोकने के एक़दामात किये गए थे।

औरतों के सामाजिक उत्पादन में भागीदारी के महत्व को उस वक़्त किस रूप में और कितने संजीदे तरीक़े से लिया जा रहा था वह इसी किताब में दर्ज़ अमानुल्लाह की बेगम बीबी सुरैया के कथन से लगाया जा सकता है।

बीबी सुरैया ने सन् 1926 में ही कहा था कि "यह सोचना ग़ैरमुनासिब होगा कि मुल्क को सिर्फ़ मर्दों की ज़रूरत है। औरतों की भी भागीदारी उतनी ही ज़रूरी है। इस्लाम के शुरुआती दिनों का इतिहास गवाह है किस तरह औरतें अपने तयीं अनमोल ख़िदमात को अंजाम देतीं थीं। उन मिसालों के ज़रिए ही हम सीखते हैं कि अपने क़ौम की तरक़्क़ी के लिए हम सबको ही मिलकर भागीदारी करनी होगी।"

-शाह अमानुल्लाह और बेगम सुरैया

गांधी का रामराज्य

शैलेंद्र श्रीवास्तव

गांधी जिस रामराज्य की बात करते थे वह न्याय पर आधारित एक मुकम्मल समाज की अवधारणा थी। वह पृथ्वी पर धर्म का राज्य था। वह स्वराज से भी आगे बढ़कर राजनीतिक रूप से आत्मनिर्भर व्यवस्था थी। वह बराबरी पर आधारित एक लोकतांत्रिक राज्य था जहां राजा सचमुच अपनी प्रजा का सेवक था और संप्रभुता राज्य नहीं समाज के पास थी।

वे राम के नाम पर ईश्वर यानी सत्य का राज्य कायम करना चाहते थे। संभवतः एक पारदर्शी और जवाबदेह लोकतंत्र वही होता है जिसकी स्थापना सत्य पर आधारित हो। जहां न तो राजा झूठ बोले और न ही प्रजा झूठ सहे। जहां झूठ सबसे निंदनीय कार्य समझा जाए।

उन्होंने अपनी अवधारणा को स्पष्ट करते हुए 1929 में यंग इंडिया' में लिखाः---- मैं अपने मुस्लिम मित्रों को सचेत करता हूं कि मेरे रामराज्य शब्द के प्रयोग पर वे किसी प्रकार की गलतफहमी में न आएं। मेरे लिए रामराज्य का अर्थ हिंदू राज नहीं है। मेरे लिए रामराज्य का अर्थ दैवीय शासन है। एक प्रकार से ईश्वर का राज्य है। मेरे लिए राम और रहीम एक ही हैं। मैं सत्य के अलावा और किसी को ईश्वर नहीं मानता। मेरी कल्पना के राम कभी इस धरती पर आए थे या नहीं लेकिन रामराज्य का प्राचीन आदर्श निस्संदेह एक प्रकार से सच्चे लोकतंत्र का नमूना है। वह ऐसी शासनव्यवस्था है जहां पर सबसे सामान्य नागरिक को भी लंबी और महंगी प्रक्रिया से गुजरे बिना त्वरित न्याय की उम्मीद बनी रहती है।'

एक जगह अपने रामराज्य की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा....आधुनिक युग के संदर्भ में कहा जा सकता है कि पहले खलीफा ने रामराज्य स्थापित किया। अबू बकर और हजरत उमर ने करोड़ों के राजस्व इकट्ठा किए फिर भी निजी तौर पर वे फकीर की तरह ही रहते थे।'

उन्होंने और स्पष्ट करते हुए 1946 में हरिजन में लिखा.... (मैं रामराज्य शब्द का प्रयोग इसलिए करता हूं) क्योंकि यह एक सुविधाजनक और सार्थक अभिव्यक्ति वाला मुहावरा है। इसके विकल्प में कोई दूसरा शब्द नहीं है जो लाखों लोगों तक मेरी बात को इतने प्रभावशाली ढंग से पहुंचा दे। जब मैं सीमांत प्रांत का दौरा करता हूं या मुस्लिम बहुल सभा को संबोधित करता हूं तो मैं अपने भाव को व्यक्त करने के लिए खुदाई राज शब्द का प्रयोग करता हूं। जब मैं ईसाई जनता को संबोधित करता हूं कि तब मैं धरती पर परमात्मा के राज की बात करता हूं।'

गांधी ने 1937 में अपने रामराज्य की व्याख्या करते हुए कहा कि यह नैतिक शक्ति पर आधारित लोक संप्रभुता है। यह अंग्रजों के साम्राज्य या सोवियत संघ की शासन प्रणाली या नाजियों की शासनप्रणाली से अलग है।

बाद में 1946 में गांधी ने रामराज्य का ठोस स्वरूप स्पष्ट किया। ब्हरिजन' अखबार में स्वतंत्रता की व्याख्या करते हुए उन्होंने लिखाः-मित्रों ने अक्सर मुझसे स्वतंत्रता की व्याख्या करने को कहा है। .....मैं कहना चाहता हूं कि मेरे सपनों की स्वतंत्रता का अर्थ रामराज्य है। यानी धरती पर ईश्वर का राज्य। मुझे नहीं मालूम की वह स्वर्ग में कैसा होगा। मेरी इच्छा भी उतनी दूर की व्यवस्था को जानने की नहीं है। अगर वर्तमान आकर्षक है तो भविष्य उससे बहुत अलग नहीं होगा। मेरे लिए ठोस रूप से स्वतंत्रता के आयाम राजनीतिक, आर्थिक और नैतिक हैं। राजनीतिक का अर्थ है कि अंग्रेजी सेना को हर रूप में यहां से हटा दिया जाए। आर्थिक का अर्थ है अंग्रेज पूंजीपतियों से पूरी तरह आजादी और भारतीय पूंजीपतियों से भी स्वतंत्रता। दूसरे शब्दों में सबसे छोटा व्यक्ति भी सबसे बड़े के बराबर महसूस करे। यह तभी हो सकता है जब पूंजी और पूंजीपति अपने कौशल और पूंजी को सबसे कमजोर तबके के साथ बांटें।

नैतिक का मतलब है सेना और रक्षा बलों से स्वतंत्रता। मेरी रामराज्य की अवधारणा में अंग्रेजी सेना को हटाकर भारतीय सेना को उसकी जगह स्थापित कर देना नहीं है। जिस देश का शासन उसकी राष्ट्रीय सेना से संचालित होता है नैतिक रूप से कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। इसलिए उस देश का सबसे कमजोर व्यक्ति पूरी नैतिक ऊंचाई तक कभी नहीं पहुंच सकता।'

फोर्ड के भारत से जाने पर सरकार से सवाल की जगह मामले पर पर्दा डाल रहा है मीडिया

गिरीश मालवीय

मीडिया ने अपना घटियापन खुलकर दिखाना शुरू कर दिया, जैसे ही फोर्ड मोटर्स द्वारा भारत में कामकाज समेटने की खबर आयी, इस घटना पर देश के प्रमुख अखबार नवभारत टाइम्स ने यह खबर लगाई कि 'फोर्ड ने रतन टाटा को औकात दिखाने की कोशिश की, टाटा मोटर्स ने ऐसे रौंदा कि ताले लग गए।'

यानी सरकार से इस बात का जवाब मांगने के बजाए कि फोर्ड जैसी कम्पनी भारत में बिजनेस क्यों बंद कर रही है। मीडिया देश की जनता को बरगलाने में लगी है कि फोर्ड तो इसलिए भाग खड़ी हुई क्योंकि उसे टाटा मोटर्स ने पीट दिया उसे धूल चटा दी।

परसाई ने लिखा है 'शर्म की बात पर हम ताली पीटते हैं इस समाज का क्या ख़ाक भला होगा'।

पिछले दिनों देश की सबसे बड़ी ऑटो कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया के चेयरमैन आरसी भार्गव ने वाहन उद्योग संगठन सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चरर्स (SIAM) के 61वें सालाना सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा था कि सरकारी अधिकारी ऑटो इंडस्ट्री को सपोर्ट देने के बारे में बयान तो बहुत देते हैं, लेकिन जब बात सही में कदम उठाने की आती है, वास्तव में कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा, 'हम ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं, जहां इस उद्योग में लंबे समय से गिरावट आ रही है'।

आरसी भार्गव ने इस भाषण में एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा दिया, उन्होंने कहा कि अगर वाहन उद्योग को अर्थव्यवस्था तथा विनिर्माण क्षेत्र को गति देना है, देश में कारों की संख्या प्रति 1,000 व्यक्ति पर 200 होनी चाहिए जो अभी 25 या 30 है। इसके लिए हर साल लाखों कार के विनिर्माण की जरूरत होगी।

इसका अर्थ यह है कि पैसेंजर कार मार्केट में ग्रोथ की बहुत बड़ी संभावना अभी भी मौजूद है ऐसे में फोर्ड का जाना मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर प्रश्नचिन्ह लगने के समान है लेकिन नहीं, मीडिया इस घटना को ऐसा दिखा रहा है कि फोर्ड टाटा मोटर्स से डरकर भाग खड़ा हुआ।

मारुति सुजुकी के चेयरमैन आरसी भार्गव ने इस भाषण में मंच पर उपस्थित अमिताभ कांत (नीति आयोग के सीईओ) से पूछा कि, 'क्या हम आश्वस्त हैं कि देश में पर्याप्त संख्या में ग्राहक हैं जिनके पास हर साल लाखों कार खरीदने के साधन हैं? क्या आय तेजी से बढ़ रही है? क्या नौकरियां बढ़ रही हैं?

हम जानते ही हैं कि छोटी बजट कारों की खरीद मुख्यतः मध्यम वर्ग करता है, अगस्त में 15 लाख नौकरी जाने की खबर आई है यानी देश का मध्य वर्ग बुरी तरह से परेशानियों से जूझ रहा है। फोर्ड भी समझ गयी है कि इन तिलों में तेल नहीं है इसलिए उसने अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया है।